

प्रेषक,

सुभाष कुमार,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 17 / फरवरी, 2009

विषय:- मै0 मुक्ता ड्रग्स प्रा0लि0 को ग्राम सालियर साल्हापुर मु0 परगना भगवानपुर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार में फार्मास्यूटिकल उद्योग की स्थापना हेतु कुल 0.2040 है0 भूमि क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-450/भूमि व्यवस्था-भू0क्र0- VIII दिनांक-14.06.08 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मै0 मुक्ता ड्रग्स प्रा0लि0 को ग्राम सालियर साल्हापुर मु0 परगना भगवानपुर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार में फार्मास्यूटिकल उद्योग की स्थापना हेतु कुल 0.2040 है0 भूमि क्रय की अनुमति उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत आपके उपरोक्त पत्र के द्वारा अनुमोदित/संस्तुत खाता गाटा/खसरा संख्या-506 एवं 507 के अनुसार निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

- 1- कंता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।
- 2- कंता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।
- 3- कंता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (औद्योगिक प्रयोजन-टैबलेट कैप्सूल, ड्राई सीरप) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

- 4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।
- 5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।
- 6- शासन द्वारा दी गई भूमि कय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।
- 7- कय की जाने वाली भूमि का भू- उपयोग यदि औद्योगिक से भिन्न हो तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर जी0आई0डी0सी0आर0-2005 में दिये गये नियमों/मानकों के अनुसार एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए औद्योगिक प्रयोजन हेतु भवन निर्माण का प्लान सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 8- इकाई द्वारा फार्मा उत्पादों (टेबलेट कैप्सूल, ड्राई सीरप) का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है जो थ्रस्ट सेक्टर के अन्तर्गत है। भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय(औद्योगिक नीति एवं संस्वर्द्धन विभाग) के कार्यालय झाप दिनांक-07.01.2003 के संलग्नक-2 के क्रमांक-12 में फार्मा प्रोडक्ट्स किया कलापो/उत्पादों को घोषित औद्योगिक क्षेत्रों से बाहर विशेष पैकेज का लाभ अर्हता पूर्ण करने पर अनुमन्य होगा।
- 9- इकाई द्वारा कय की जाने वाली भूमि का उपयोग फार्मास्यूटिकल उत्पादों (टेबलेट, कैप्सूल, ड्राई सीरप) की स्थापना हेतु ही किया जायेगा।
- 10- प्रस्तावित उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।
- 11- प्रश्नगत इकाई में पूंजी निवेश/निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अग्निशमन विभाग एवं ड्रग कन्ट्रोलर से ड्रग लाइसेंस प्राप्त किये जाने हेतु नियमानुसार अनापत्ति/सहमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- 12- प्रस्तावित स्थल पर अवस्थापना विकास से सम्बन्धित कार्यों का दायित्व सम्बन्धित इकाई का होगा।
- 13- प्रश्नगत उद्योग की स्थापना के सम्बन्ध में स्पॉट जोनिंग क्षेत्र के लिए निश्चित सिद्धान्त/नीतियों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।



- 14- उक्त इकाई द्वारा Industrial wastage/effluent की व्यवस्था भी करनी अनिवार्य होगी।
- 15- सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू-उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी यह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।
- 16- किसी भी दशा में प्रस्तावित कंटाओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि कय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।
- 17- भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 18- योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/ संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियों/स्वीकृतियों प्राप्त कर ली जायेगी।
- 19- उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तों का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन हाने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया इस सम्बन्ध में तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)  
प्रमुख सचिव।

पृ०प०सं०-359 /संमदिनांकित/2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेश के उद्योग विभाग से सम्बन्धित समस्त बिन्दुओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
- 3- सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 5- निदेशक, उद्योग, इन्ड्रिस्ट्रियल इस्टेट, पटेलनगर, देहरादून।
- 6- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीडा, 2-न्यूकैन्ट रोड, सिडकुल, देहरादून।
- 7- श्री राजकुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश निदेशक मै० मुक्ता ट्रस्ट प्रा०लि० 36-37 सज्जन सिंह पार्क मॉडल टाउन जिला पानीपत हरियाणा।

- 8- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
- 9- प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(सन्तोष बहनी)  
अनु सचिव।